बनकरों के कल्याण के लिए हैं, इस प्रकार है :—

(1) कार्यशाला-सह-आवास योजना ।

(2) थ्रिफ्ट फंड योजना और समूह बीमा योजना ।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत जारी की गई सहायता इस प्रकार है :—

लाख रुपयों में

	1990-91	1991-92
1. कार्यशाला-सह-आवास योजना	300.02	324.17
2. थ्रिफ्ट फंड योजना और समूह बीमा योजना ।	119.89	82.06

पावरलूम सर्विस केन्द्र

2453. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पावरलूम सर्विस केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिए है ;

(ख) यदि हां, तो ये पावरलूम सर्विस केंद्र देश के कौन-कौन से हिस्सों में खोले जायेंगे ; और

(ग) उन स्थानों पर खोले जाने वाले केंद्रों का ब्यौरा क्या है जहां कपड़ा मिलों के बंद होने के कारण बेरोजगारी फैली

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रस्तावित विद्युत करघा सेवा केन्द्र की अवस्थिति का निर्धारण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है । विद्युत करघा सेवा केन्द्रों की अवस्थिति के निर्धारण के लिए मुख्य मानदंड उस क्षेत्र के विद्युत करघों की संख्या पर आधारित होता है ।

Handloom sector facing competition from Mill sector

2454, SHRI SHIV PRATAP MISHRA; Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that handloom sector which provides employment to nearly 2 crore people is facing stiff competition from machine sector;

(b) whether Government are aware that earlier each mill was supposed to produce hank yarn as 50 per cent of its produce but now it has been changed to produce 50 per cent for the mill sector as a whole; and

(c) if so, the steps Government propose to lake to provide relief to the handloom industry?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY, (a) to (c) Yes Sir. The Government has been taking a number of measures to provide relief to the handloom industry such as strict enforcement of the reservation orders for the hadloom sector, supply of yarn at mill rate prices, provision of work-sheds and work-shed-cum-houses to handloom weavers, implementation of welfare schemes like Thrift Fund and Group Insurance.